पृ0पत्र संख्या-स्था-।-सामान्य- निर्वाचन- 948 /वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग) लखनऊ :: दिनांक 15 जून, 2016

विषयः- राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन (NERP) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या-1800/सी0ई0ओ0-4-11/4-2016 दिनांक 20-5-2016 के साथ राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन(NERP) के अन्तर्गत पल्टीपल/रिपीटेड नाम एवं निर्वाचक नामावलियो में विद्यमान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों मे संशोधन किए जाने विषयक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 27-2-2016 की प्रति तथा मतदाता सूची से नाम अपमार्जन किए जाने सम्बन्धित फार्म-7 की प्रति प्रेषित करते हुए, जिन कर्मचारियों का एक से अधिक स्थानों की निर्वाचक नामावली में नाम विद्यमान है तथा यदि उनके पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र है तो ऐसे मल्टीपल/रिपीटेड नाम वाले कर्मचारियों को उक्त फार्म वितरित कराने की कार्यवाही कराते हुए यह सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गई है कि वे जहॉ पर कार्यरत है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों की निर्वाचक नामावलियों से अपना नाम हटाए जाने के अनुरोध फार्म-7 पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस जिले के जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दें।

2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 20-5-2016 एवं आयोग के निर्देश पत्र दिनांक 27-2-2016 तथा मतदाता सूची से नाम अपमार्जन किए जाने से सम्बन्धित फार्म-7 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय के अधिष्ठान अनुभाग के माध्यम से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय,

(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0 प्र0 के उक्त दि0 20-5-2016 एवं आयोग के निर्देश पत्र दि 27-2-2016 तथा मतदाता सूची से नाम अपमार्जन किए जाने से सम्बन्धित फार्म-7 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0लखनऊ ।
2. एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,उ0प्र0।
3. कमिश्नर,वाणिज्य कर(कैम्प )उ0प्र0।
4. एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
5. अपर निदेशक, कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान,वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ ।
6. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-।(उच्च न्या0कार्य)वाणिज्य कर,इलाहाबाद।
7. एडीशनल कमिश्न ग्रेड-2(उच्च न्या0कार्य)वाणिज्य कर,लखनऊ ।
8. समस्त अनुभाग अधिकारी,वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
9. असिस्टेन्ट कमिश्नर(कम्प्यूटर)वाणिज्य कर,मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट हेतु ।

(सुनील कुमार राय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।

महत्वपूर्ण

# मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या–1800 / सी0ई0ओ0–4–11 / 4–2016 लखनऊः दिनांकः 20 मई, 2016

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   प्रदेश मुख्यालय स्थित भारत सरकार के कार्यालय
   लखनऊ।
4. समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको के प्रदेश स्तरीय प्रमुख,
   लखनऊ।

विषय– **राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन (NERP) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन (NERP) के अन्तर्गत मल्टीपल / रिपीटेड नाम एवं निर्वाचक नामावलियों में विद्यमान विभिन्न प्रकार की त्रुटियों में संशोधन किए जाने के निर्देश दिए गए है। सम्प्रति राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन का यह कार्यक्रम वर्तमान में गतिमान है।

2– इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के अन्तर्गत मुख्य रूप से निर्वाचकों के एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक नामावलियों में नाम होने के मामलों को उनके द्वारा स्वैच्छिक प्रकटन (Voluntary disclosure) किए जाने की दशा में सम्बन्धित ईआरओ द्वारा कार्यवाही किया जाना तथा अभिलेखीय आधार पर निर्वाचकों से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि की त्रुटि में संशोधन की कार्यवाही इत्यादि करना है। प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध हैं। जहां मतदाता पहचान पत्र नम्बर, नाम आदि से खोजने की सुविधा उपलब्ध है।

3– भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी का सहयोग प्राप्त किया जाए। आप सहमत होंगें कि शासकीय कर्मचारियों के नाम नियमों के विपरीत एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूचियों में दर्ज होना एवं विद्यमान रहना किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। मैं आयोग के निर्देश दिनांक 27.02.2016 की एक प्रति तथा मतदाता सूची से नाम अपमार्जन किए जाने से सम्बन्धित फार्म–7 की 10–10 प्रतियां इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर रहा हूँ कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत जिन कर्मचारियों का एक

से अधिक स्थानों की निर्वाचक नामावली में नाम विद्यमान है तथा यदि उनके पास एक से अधिक मतदाता पहचान पत्र है तो ऐसे मल्टीपल/रिपीटेड नाम वाले कर्मचारियों को उक्त फार्म वितरित कराने की कार्यवाही कराते हुए यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि वे जहां पर कार्यरत हैं उसके अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों की निर्वाचक नामावलियों से अपना नाम हटाए जाने के अनुरोध फार्म–7 पर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उस जिले के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दें। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–17 एवं 18 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार निर्वाचक नामावली में नाम रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा तथा धारा–31 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति इस विषय में मिथ्या घोषणाएं करता है, तो वह कारावास एवं जुर्माने से दंडनीय होगा।

4– आप अवगत हैं कि प्रदेश में शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो स्वयं कम्प्यूटर के प्रयोग के अभ्यस्त हैं तथा इनके द्वारा स्वयं ही अपने एवं अपने परिवार के मतदाताओं के नाम की जानकारी ऊपर उल्लिखित वेबसाइट से की जा सकती है और अन्य का सहयोग भी किया जा सकता है। आप यह भी अवगत हैं कि शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए इस कार्यक्रम के सफल संचालन में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है।

5– प्रस्तुत प्रसंग में यह भी कहना है कि कृपया राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों के परिशोधन कार्यक्रम के बारे में तथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने विभाग के अधिष्ठान पटल के माध्यम से मुख्यालय एवं फील्ड कार्यालयों हेतु समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें। फील्ड स्तर पर इस कार्य में सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के सभी जिला निवाचन अधिकारियों व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के मोबाइल नम्बर आदि की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बेवसाइट http://ceouttarpradesh.nic.in/ पर उपलब्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के टॉल फ्री नम्बर 1800–180–1950 से भी इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**संलग्नकःयथोपरि।**

भवदीय,

**(अरुण सिंघल)**
**मुख्य निर्वाचन अधिकारी**

**संख्याः1800(1)/सी0ई0ओ0–4 तद्दिनांक–**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

**(अरुण सिंघल)**
**मुख्य निर्वाचन अधिकारी**

भारत निर्वाचन आयोग
*Election Commission of India*

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 23/2016-ERS

Dated: 27th February 2016

To,

The Chief Electoral Officers of All States/UTs
(Except Assam, Bihar, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal)

Subject: National Electoral Rolls Purification (NERP) 2016 drive to improve the health of the Electoral Rolls (ERs) and to rationalize the Polling Stations (PSs) boundaries and location - regarding.

Sir/Madam,

The purity of an electoral process is directly dependent on the health of the electoral rolls. It has been the Commission's constant endeavour to improve the fidelity of Electoral Rolls by focused efforts to improve the enrolment and remove multiple entries & data errors by effective use of technology and requisite facilitations and laid down procedures. These activities related to ER Purification coupled with the effective SVEEP strategies will educate and motivate voters to volunteer to get their multiple entries removed, get the errors and addresses corrected and updated. The Commission also decided to address the polling station related issues such as rationalization in a holistic and comprehensive way.

2. In just concluded SR 2016 many gaps identified and communicated to CEOs and to DEOs through CEO. These gaps also need to be closed to the extent possible.

3. With a view to achieving the above objective, the Commission has decided to launch an intensive drive "National Electoral Rolls Purification (NERP) 2016 which will include enrolment of all eligible citizens and removal of repeated and multiple entries, entries of dead, shifted & absent voters, correction of errors in EPIC and removal of other data errors. During this drive repeat images will also be corrected, missing photographs will be collected; poor quality of images will be replaced by a good quality photographs. The gaps of SR 2016 will be closed to the extent possible.

4. The Commission has further decided to standardize and rationalize the sections with in a part, Part/PS boundaries and Polling station locations keeping in view the voters' convenience and facilities available along with the ease of conduct of poll, with due consultation with stakeholders' including public and political parties. In this process, (i) mapping of the Basic Minimum Facilities ( BMFs) for voter's facilitation and convenience , (ii) preparation of improved rough sketch Maps (Nazari Naksha) using IT techniques like CAD and GIS Maps, (iii) PS images, (iv) key map for reaching the PS and CAD drawing with model lay out on poll day should be done for each PS.



5. **NERP 2016 drive is to be launched on 1st March, 2016 and to be completed on or before 31st August, 2016. Month of March will be used as a preparatory phase and actual work will commence from 1st April, 2016.**

6. The Commission has directed that the Census 2011 databases projected to 2016 should be used as a benchmark to compare and analyse the critical gaps in the ERs with respect to the age Cohort, Elector/Population ratio and Gender ratio. Higher youth registration (18-19 years' age group) and 100% EPIC/PER are to be kept as the main focus areas.

7. Your attention is invited to the Commission's letter No. 23/2016-ERS, dated 3rd February 2016, and the Video Conference discussion with the Chief Electoral Officers on 5th February 2016. Broad guidelines to implement NERP 2016 are follows:

**7.1 AIMS AND OBJECTIVES**

**(a) Electoral Roll related Activities**

1- Removal of gaps in E/P ratio and gender ratio with focus on maximization of enrolment in 18-19 age groups.
2- Ensuring 100% coverage of EPIC/PER.
3- Ensuring good quality photographs, if necessary, by replacing blurred, poor quality and repeat and non human images,
4- Identification and corrections of various types of inaccuracies/errors in electoral rolls using IT tools and then making necessary correction in Electoral database.
5- Removing from the electoral rolls any dead/shifted/multiple entries, gainfully using IT applications.
6- Collection of contact details of electors and/ or their family members. (It is option of the elector to disclose. If disclosed, he would get many Election related services. The data, under no circumstance to be put in public domain or shared with any person or authority)
7- Updation of control tables of ER database.

**(b) Polling station related Activities**

1- Standardization of sections and modification of the part boundaries of existing polling stations to make a polling station compact in perspective of polling area with voters strength of about 1200 in rural area and about 1400 in urban area,

3- To ensure that voters are not required to travel long distances (over 2KM) and/or cross geographical barriers like river, ravines, rivulets, spills, deep forest etc. to reach PS.

4- To identify and map alternative locations within the polling areas with BMFs etc.

5- To make Rough Sketch Maps (*Nazri Naksha*) as a precise PS Map drawn using CAD with correct dimensions and model layout, with BMF information, actual images of PS, Google- Map & street view and Key map on how to reach, wherever felt necessary.

7.2 Electoral Roll Component of NERP 2016 Drive

(A) STRATEGIES

(a) Identification of the Gaps and finalising the strategy and time line

i. CEO/DEOs/EROs shall do statistical analysis of data of Format 1-8 in respect of finally published electoral rolls with reference to 01.01.2016 as the qualifying date in order to find out major gaps in terms of E/P ratio, gender ratio, age co-hart imbalances, particularly of 18-19 years age group, abnormal increase or decrease in number of voters in any area, <100% PER/EPIC in ACs/ PSs and service electors. No need to emphasize that the analysis should be done with due care and promptitude. For a better analysis, previous years' data should also be taken into consideration for better appreciation of the scenario by comparing using charts etc. If analysis is done at micro level i.e. polling station level, the gaps may clearly manifest which hide at macro level i.e. State/District or AC level. Since census data of 2011 including population age details is already available, the population projection to 2016 should be done on 2011.

ii. The above said analysis of data should be done by the EROs & AEROs who after discussions with BLOs & Supervisors should give analytical note to DEO concerned who shall discuss with EROs& AEROs of electoral data in respect of all ACs under their jurisdiction. After critical gaps are determined, then please check, if any cogent and logical reasons like migration due to socio economic or natural calamities etc. and/or cropping up of new colonies/habitats are there to answer the gaps. If so mention it in the note. The EROs should forward their notes to DEO concerned who shall , after discussing the same with EROs and any other concerned authorities, forward a composite analytical note to CEO along with strategies to address the issues. Finally, the CEO shall, having reviewed and analyzed district wise reports, to prepare State analytical note and chalk out necessary strategies to address the gaps that need to be filled up. The gaps should be described in quantitative terms.

iii. Chalking out suitable strategies to address the critical gaps by sustained efforts by field election machinery good training and publicity materials should be prepared under SVEEP and properly disseminated.

iv. The Commission desires that the above activity should be completed by 25th March and an AC wise action plan of the state with identified gaps, strategy and time line etc. after completing following three stages should be sent to ECI by this.

- Analysis by EROs & AEROs (with Format 1 to 8) along with BLOs (with BLO register) & Supervisors.
- Analysis and review by DEOs along with EROS & AEROs
- Review by CEO with DEOs

v. After this is done, a fortnightly action plan of activities to bridge the identified gaps with suitable strategies within a fixed time line should be prepared and forwarded to ECI. By 31st August 2016, the aims and targets in this regard have to be achieved.

vi. A proper assessment of resources needed for the purpose should also be done.

vii. Training component is a critical part so CEO, in consultation with ECI training division chalk out a plan for it

(b) Purification of Electoral Rolls

The Commission appreciate that a lot of work has been done to correct the ER errors and removal of repeat/multiple entries during previous continuous updating and the last revision of electoral rolls in the States/UTs based on voluntary disclosure, de-duplication software's reports for House to House visit and field verification by BLOs. However, some work in this regard is still unfinished. The Commission, has therefore, decided to continue the process of error correction and repeat/ multiple entries removal following due procedure under the law in NERP 2016 drive during ongoing continuous updating of electoral rolls so as to achieve error free electoral rolls. The strategy and time lines should be stated in the action plan being sent March, 2016.

**(1) Addressing the errors in ERs:** Please identify the entries with probable errors of the 17 types mentioned below by running EDS (Error Detecting Software) on the ER data base centrally at CEOs level.

i. Voter first/last name is Null/Junk Characters

ii. Part No. is Null/Junk Characters

iv. Section No. is Null/Junk Characters
v. House No. is Null/Junk Characters
vi. Voter relationship #M,F,H,O or m,f,h,o/Junk Characters
vii. Voter Sex M,F,TG(Third Gender)/Junk Characters
viii. Voter gender is male but relationship is H/Junk Characters
ix. Voter relatives name is blank/Junk Characters
x. EPIC no. is less than 10/Junk Characters
xi. Age is less than 18 or greater than 100/Junk Characters
xii. Photograph exists but ID Card No. is not available
xiii. ID Card No. exists but Photograph is not available
xiv. List of Records where EPIC no. is repeating
xv. Voter gender is female but relationship is F/D for voter age > 30
xvi. Voter Status type #N,E,S,M,R or n,e,s,m,r/Junk Characters
xvii. Number of sections having no voters

**(2) Identification of multiple/repeat entries/multiple EPIC numbers**

i. The software to detect possible multiple/repeat entries should be run on the ER data base centrally at CEO level to (a) Within parts, (b) Across parts in an AC, (c) Across ACs in a district, (d) Across districts in a state. The IT division of ECI is concurrently, making/has made National Register of Errors, and it would be made available to CEO. IT division is issuing instructions in this regard

ii. Also, using appropriate software, cases of repeated EPIC numbers and repeated images should be culled out. The IT division of ECI is also, concurrently, doing the similar exercise on National database and would share its results with CEOs soon.

iii. This has to be followed by necessary field verification, wherever needed, for corrective actions.

It is pointed out that

i. Cases where same EPIC number is allotted to more than one electors- In this case, after ERO satisfies himself that such persons are different and residing at different places, then the elector who was issued EPIC first will retain his EPIC and the other elector/s who got EPIC later on with same EPIC number, shall be issued, EPIC with new EPIC number, free of cost, after taking back old EPICs which should be disposed of by cutting into pieces after keeping a proper record.

ii. Cases of different EPIC numbers but images are same- In such cases proper verification must be done by BLOs, if the entries pertain to same person. In that case, it should be treated as a case of multiple entries and accordingly be disposed of. If it is found that they are different persons, then the incorrect image should be replaced after obtaining Form 8 with correct photograph from the concerned elector/s. New EPICs, wherever necessary, should be issued free of cost, after taking back old EPICs which should be disposed of by cutting into pieces after keeping a proper record.

iii. The IT division of ECI will issue SOP for preparation of EPICs so as to eliminate any chance of repeated EPIC numbers or repeated images in different EPICs. Image quality parameters are being defined and would be intimated to you soon.

**(3) Dead Voters:** The death records of past 5 years should be obtained from the concerned authorities that are authorized under state law to maintain such records. Thorough verification in concerned parts(s) should be made to identify any possible entry of the dead voters in the rolls, and if found so, then the entry should be flagged in the concerned part /BLOs register for further field verification by the BLO.

**(C)Verification**

1. The aforesaid lists would need to be verified by BLOs/other field functionaries by house to house verification (H2HV) during a specific period in one go, to be decided by the CEO keeping in view various factors in mind. The BLO should visit the household with BLO register/roll and the lists to be verified. It is suggested that if possible, the H2HV of lists should be done on a specific common date in entire state duly publicized to eliminate chance of the elector sneaking to other place, after verification at one place is over, so as to present at the other place too. If needed it can be repeated on any other date also.

2. The BLOs/other field functionaries should also collect, during their H2HV of contact details of electors and/ or their family members like Mobile No. and Type (Smart phone/ Text Based),Whether Primary and /or alternate, Land line No. and E-mail address and Parents EPIC details. It is made amply clear that furnishing of these information is purely voluntary and since it is exclusively personal, in no way and under no circumstance it shall be displayed in public domain in any manner either electronically or otherwise and it shall be personal responsibility of concerned CEO/DEO.

**(D)Actions by EROs**

After the lists of errors/shifted/dead/multiple entries etc. are got verified, the EROs concerned shall ensure that all Forms for inclusion and transposition in form 6,6A,& 8A, deletion through form-7 or 8 for correction in entries received from citizens are disposed of and Suo moto actions, wherever required, are taken strictly following statutory provisions read with ECI guidelines Wherever possible Form 7,8 or 8A should be obtained.

The BLO is a verifying official and the power to accept/reject an application in Form 6,6A,7 or 8 , lies with ERO/AERO only who has to pass appropriate order in each individual case , after satisfying himself.

ECI instructions on data security have to be observed strictly. In case it is found that the ERO has shared digital signature to vendor or any other person, he would expose himself for strict disciplinary action by ECI.

**(E) Monitoring-**

CEO is to keep a close watch on the progress of NERP 2016. Necessary super checks should be done as per ECI guidelines. It shall be the personal responsibility of DEOs to ensure that prescribed information is uploaded daily in the dashboard created for Special ER purification drive on ECI web site and to read the comments/ directions of the Commission for immediate action and compliance.

**(F) Publicity and related issues**

1- A comprehensive publicity campaign through all types of mass communication shall be organized to motivate the voters to voluntarily come forward to disclose any repeat/ multiple entries in ERs and repeat EPIC no. and to the relatives and neighbours of dead persons to apply for the deletion of such entries from ERs.

2- Meeting with recognized political parties at state /district level should be held during the drive inviting their specific complaints which will be verified in a time bound manner. Further, the political parties should be requested to appoint Booth Level Agents (BLAs) for all polling stations and to assist the Booth Level Officers (BLOs) during special ER purification drive in identification of repeat/ multiple entries or dead electors.

3- BLAs of the recognized political parties may be intimated through political parties that they can see that list with the BLO. An one day meeting of BLOs and BLAs should be held for exchange of relevant information.

4- The Polling station wise lists of repeated/ multiple entries, repeat EPIC nos. and dead voters shall be read over in the meeting of the concerned Wards or RWAs or the Gram Panchayat / Urban local body unit in presence of members of BAGs on a prefixed date. A proper record /minutes of such meetings should be kept and necessary action should be taken by the EROs to redress the issues.

5- A copy of the lists of probable repeat/ multiple entries, repeat EPIC nos. and



of CEO and DEOs and the URL/ web link to be informed in writing to the political parties and their valuable inputs to be invited. A media briefing will also be done at the State and District levels in this respect.

**(G) Complaint Redressal**

A robust mechanism for complaint redressal should be set up using suitable IT technologies. If any complaint from political parties or any other stake holders is received then after taking necessary action, a suitable reply must be given to them and a proper record of the complaints received and reply given should be maintained.

**(H) Training**

Special training shall be imparted to all electoral officers down to BLO level by the respective CEOs. The CEOs shall prepare and distribute a booklet on special ER purification drive to all officials and develop effective publicity material for all stakeholders. Training of IT applications shall also be arranged by CEO at State HQs. Director (IT) /(Trg) of ECI may be kept in loop in this regard.

**8. Special drive for rationalization of Polling Stations:**

The Commission has observed that frequent changes in location of the polling stations or its (part) boundary should be avoided. Hence, in partial modification of its existing policy to have polling stations rationalized every year, it has been decided that thorough review of the list of polling stations or rationalization of polling stations should be done either in election year or one year prior to that. Hence, there is a need to relook the list of existing polling stations so that it caters to the needs of next few years.

In case of increase in electors beyond the permissible limit, auxiliary polling stations may be set up. To address the issue of development of new colonies, and deterioration in condition of existing building availability of suitable new buildings, status of BMF, change in geographical location etc., if absolutely essential, the CEO may send proposals accordingly to the ECI for approval.

Hence all CEOs may during the NERP-16 undertake the following -

1) Providing a polling station to new colonies that have cropped up during intervening time.
2) Converting the auxiliary polling stations into main polling station. This may need re-distribution of electors between them.
3) Section rationalisation and re-assigning of electors from one polling station to other polling station, if needed to make the polling area of the polling station compact. There should not

4) To carry out physical verification of existing and probable polling stations and also check the status of BMFs.

5) The rationalization should be done after 100% physical verification of the existing and probable polling station locations and the relevant parts of the electoral rolls.

While undertaking 100% physical verification, all existing polling stations must be inspected as per existing guidelines which include the following

- Whether polling station area has been correctly and fully described in the existing polling station list.
- Whether polling station is situated outside the polling area;
- Whether voters have to cross river/canals/ravines etc. to reach the polling station;
- Whether voters are required to cover distance of more than 2 KMs to reach polling station;
- Whether the polling station location has more than 2 polling stations in rural areas or more than 4 polling stations in urban areas;
- Whether the building is dilapidated or dangerous;
- Whether the minimum area of polling station room is 20 sq meters and whether it is having two doors;
- Whether polling station is on 1st floor or above;
- Whether polling station is located in a police station/hospital/ Dharamshala/temple or a religious place;
- Whether office of any political party is situated within 200 meters from polling station location;
- Whether the building has an electric connection;
- Whether ramps have been provided for physically challenged persons;
- Whether toilet and drinking water facilities exist in the polling station premises;
- Whether there is a shed to shelter the voters from sun and rain;
- Whether the polling station has telephone connection. If yes what is the phone number;
- Whether in localities predominately inhabited by minorities, weaker sections of society like scheduled caste/tribes, the polling stations are located in such a manner that such communities are not prevented from reaching the polling station and casting their votes.



Following criteria may be kept in mind while preparing proposals for creation of new polling station after physical verification as aforesaid of polling stations: -

- Optimum number of the electors that can be assigned to a polling station is 1200 in case of rural and 1400 in case of urban areas.
- All existing auxiliary polling stations should be converted into main polling stations by dividing the electoral part.
- New polling station may be proposed if a village has more than 300 electors and a suitable Government building is available for the polling station. (This needs reconsideration by ECI)
- If a new colony with a number of dwelling units has cropped up, then new polling station may be created. The electors assigned to a neighbouring polling station should be compact.
- New / separate polling station may be created in localities predominately inhabited by minorities / weaker sections of society like scheduled caste / scheduled tribes irrespective of number of electors. (The nodal officer should give a written report prepared on the basis of inputs obtained from NGOs / civil society organizations working for the welfare of such people).
- After the rationalization of polling stations is done in this manner last minute changes in the location of polling stations should not be necessary.
- Safety of polling teams and police force sent to conduct elections should also be kept in mind while proposing polling stations in Maoist or terrorist affected areas. As far as possible in these areas, polling station should be made in places which have easy and safe access. It may also be useful if polling stations are provided in a cluster in such areas to maximize and synergize the available force.
- To make Rough Sketch Maps (*Nazri Naksha*) as a precise PS Map drawn using CAD with correct dimensions and model layout, with BMF information, actual images of PS, Google- Map & street view and Key map on how to reach, wherever felt necessary.

The entire exercise has to be done within a fixed time frame as per schedule annexed in a professional manner without fear or favour, strictly in the light of statutory provisions and guidelines of Election Commission. The idea is that before next revision thoroughly revised /updated list of polling stations is prepared and got approved by the ECI u/s 25 of the RPA 1951. Please undertake the exercise in such a professional and scientific way that after the rationalization of polling stations is done, last minute changes in the

A note on use of GIS application for PS/part boundary rationalization and search of alternative buildings with better BMFs is being finalized by IT division and would soon be sent.

Kindly acknowledge the receipt of the letter by sending an email to electoral.rolls.eci@gmail.com

Yours faithfully,

(R.K.Srivastava)
Principal Secretary

13



Annexure

Rationalization of polling stations-List of activities

| SN | Activity to be carried out | Number of days required |
|---|---|---|
| 1 | Designating a senior officer as Nodal office for the work of physical verification of existing and probable polling stations | 2 |
| 2 | Detailed physical verification to verify BMF facilities and other aspects as mentioned in the letter | 30 |
| 3 | Preparation of preliminary proposal by RO and submission to DEO | 3 |
| 4 | Preparation & publication of Draft list of Polling Stations. | 3 |
| 5 | Control Table Entry to be done in the Election Commission of India's website | 14 |
| 6 | Supplying copies of the proposals of modification in the existing list of PSs to local branches of all recognized political parties. | 2 |
| 7 | Putting the draft list of polling stations on public domain and inviting suggestions from public | 7 |
| 8 | Taking decisions on suggestions made by public | 5 |
| 9 | Holding meeting with the political party representatives and MLAs/MPs to discuss the draft list of PSs. Suggestions received are to be taken in to consideration during such meeting. | 7 |
| 10 | Taking decision on suggestions made by the political party representatives and MLAs/MPs; after physical verification of the suggested locations. | 10 |
| 11 | Preparation of AC wise proposals (with medications, if any, suggested by political parties), scrutiny and forwarding by DEO, and submission thereof to the CEO along with the scrutiny sheet and the prescribed certificates. | 21 |
| 12 | Preliminary scrutiny and checking by the office of the CEO. | 30 |
| 13 | After thorough scrutiny, submission of proposal with comments/recommendation to the ECI for approval. | 15 |
| 14 | ECI's approval to the proposals submitted by the office of CEO, at least one month before the date of Draft Publication of the Electoral Roll. | 10 |
| 15 | Conveying the ECI's approval to DEOs. | 2 |
| | Total No. of Days | 161 |

-14-

-14-

# प्रारूप–7

## निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने या हटाये जाने की वांछा पर आक्षेप के लिए आवेदन
## Application for objecting inclusion or seeking deletion of name in electoral roll

**(नियम 13 (2) और 26 देखिये)**

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

..... विधान सभा / संसदीय £ निर्वाचन क्षेत्र

महोदय,

@मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं।

**या**

@मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे / *नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| I-@उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है **हिन्दी में** | नाम | | उपनाम (यदि कोई है) |
| **अंग्रेजी में** | Name | | Surname |
| @उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है | निर्वाचक नामावली के उस भाग की संख्या जिसमें उसका / उसकी नाम सम्मिलित किया गया है : | उस भाग में उसका / उसकी क्रम संख्या : | निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) |
| #II आक्षेपकर्ता का ब्यौरे **हिन्दी में** | नाम | | उपनाम (यदि कोई है) |
| **अंग्रेजी में** | Name | | Surname |
| लिंग (पुरुष / स्त्री / तृतीय लिंग) | निर्वाचक नामावली के उस भाग की संख्या जिसमें आक्षेपकर्ता का नाम सम्मिलित किया गया है : | | उस भाग में उसका / उसकी क्रम संख्या : |
| @पिता / माता / पति का नाम **हिन्दी में** | नाम | | उपनाम (यदि कोई है) |
| **अंग्रेजी में** | Name | | Surname |

**III- @आक्षेपकर्ता / @नाम हटाए जाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)**

| | हिन्दी में | अंग्रेजी में |
|---|---|---|
| मकान / गृह संख्या:<br>House/Door Number: | | |
| गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़क:<br>Street/Area/Locality/ Mohalla/Road: | | |
| नगर / ग्राम:<br>Town/Village : | | |
| डाकघर:<br>Post Office: | | |
| पिन कोड:<br>Pin Code: | | |
| तहसील / तालुक / मंडल / थाना:<br>Tehsil/Taluka/Mandal/Thana: | | |
| जिला:<br>District: | | |

**IV-*आक्षेप / *हटाए जाने का (के) कारण**

£ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं है और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामलें में।

@ पहला विकल्प निर्वाचक नामावली तैयार करने / उसका पुनरीक्षण किए जाने के दौरान सुसंगत होगा। दूसरा विकल्प, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन करने के दौरान सुसंगत होगा।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

# भाग–II वहाँ नहीं भरा जाना है जहाँ आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को हटाने की वांछा करता है।

vinenterprises 37000 Oct. 2014

**V- घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान : दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

कृपया अपनी मोबाइल संख्या / ई–मेल आई.डी. उल्लिखित करें (ऐच्छिक) / .....

टिप्पणी : **जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दण्डनीय होगा।**

**की गयी कार्यवाही के ब्यौरे**
**(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाए)**

श्री / श्रीमती / कुमारी ..... का प्रारूप 7 में निर्वाचक नामावली में श्री / श्रीमती / कुमारी ..... *के नाम को सम्मिलित किए जाने पर / *हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है / *नामंजूर कर दिया गया है।

*स्वीकार करने (नियम 18* / 20* / 26(4) £ के अधीन या उसके अनुसरण में) या
*नामंजूर करने (नियम 17* / 20* / 26(4) £ के अधीन या उसके अनुसरण में) के लिए विस्तृत कारण :

स्थान :

दिनांक : निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

£ निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाये रखने के दौरान।

**क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियाँ**

**बूथ लेबिल अधिकारी का नाम :**.....

**बूथ लेबिल अधिकारी का मोबाइल नं0 ::**.....

**मतदेय स्थल की संख्या व नाम : :**.....

**विधान सभा क्षेत्र की संख्या व नाम : :**.....

[प्रारूप 7 लगातार ..... ]

**[ यह पृष्ठ इतना मोटा होना चाहिये कि यह डाक से भेजे जाने पर क्षतिग्रस्त न हो ]**

**कार्यवाही की सूचना**

**(इस पृष्ठ का अनुभाग–।। संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जायेगा और आवेदक को उसके द्वारा इस पृष्ठ के अनुभाग–। में दिये गये पते पर डाक से भेजा जायेगा।)**

..... पहला मोड .....

**अनुभाग–।**

| डाक टिकट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय चिपकाया जायेगा। |
|---|

प्रारूप–7 में दिया गया

श्री / श्रीमती / कुमारी.....का आवेदन

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(पूरा पता) | | | | | | | | |
| मकान / गृह संख्याः | | | | | | | | |
| गली / क्षेत्र / परिक्षेत्र / मोहल्ला / सड़कः | | | | | | | | |
| नगर / ग्रामः | | | | | | | | |
| डाकघरः | पिन कोड | | | | | | | |
| तहसील / तालुक / मंडल / थानाः | | | | | | | | |
| जिलाः | | | | | | | | |

**आवेदक द्वारा भरा जाये।

.....दूसरा मोड़ .....

**अनुभाग–।।**

(क) स्वीकृत कर लिया गया है तथा श्री / श्रीमती / कुमारी.....का नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या.....के भाग संख्या.....की निर्वाचक सूची के क्रमांक.....पर विलोपित कर लिया गया है।

(ख) नामंजूर कर दिया गया है क्योंकि.....

तारीख .....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

(पता).....

.....

.....

.....फाड़ने हेतु छिद्रण.....

**आवेदन की पावती**

**श्री / श्रीमती / कुमारी.....

**पता.....

.....

से प्रारूप 7 में आवेदन प्राप्त किया।

दिनांकः

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर

(पता).....

.....

**आवेदक द्वारा भरा जाए।

# आवेदन प्रारूप–7 भरने के लिए दिशा–निर्देश

## सामान्य अनुदेश

**प्रारूप–7 कौन दाखिल कर सकता है–**

1. निर्वाचक नामावली के किसी भाग में किसी नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति या निर्वाचक नामावली के किसी भाग में पहले से ही सम्मिलित किसी नाम के विलोपन के लिए वांछा उसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है जिसका नाम पहले ही उस नामावली में सम्मिलित है।

**प्रारूप–7 कब दाखिल किया जा सकता है–**

1. निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् किसी प्रस्तावित प्रविष्टि को प्रारूप नामावली में सम्मिलित करने पर आपत्ति के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है। आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है। जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है।

2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है।

3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी अंतिम निर्वाचक नामावली से किसी प्रविष्टि के विलोपन के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है। गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए।

**प्रारूप–7 कहाँ दाखिल किया जाए–**

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहाँ प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है के साथ–साथ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है।

**प्रारूप–7 कैसे भरें–**

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहाँ उस नामावली में पंजीकृत कोई निर्वाचक, किसी प्रस्तावित प्राविष्टि को प्रारूप नामावली में सम्मिलित करने में आपत्ति करता है। खाली स्थान पर निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए।

2. **उस व्यक्ति का विवरण जिसका नाम सम्मिलित करने में आपत्ति है / उस व्यक्ति का विवरण जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है :**

दोनों विकल्पों में से पहला विकल्प निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् संगत है। दूसरे शब्दों में प्रारूप नामावली में आपत्तिजनक प्रविष्टि को नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय विलोपन सूची में दर्शाने के लिए है। दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के सतत् अद्यतीकरण के दौरान संगत है। दूसरे शब्दों में अंतिम निर्वाचक नामावली में शामिल कर ली गई किसी प्रविष्टि के विलोपन के लिए है। (कृपया प्रारूप भरते समय अनुपयुक्त विकल्प काट दें।) जिस व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि पर आपत्ति की गयी है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, निर्वाचक नामावली में उनसे संबंधित अन्य विवरण, भाग संख्या, निर्वाचक नामावली के उस भाग में प्रविष्टि की क्रम संख्या और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान–पत्र की संख्या इत्यादि भी भरी जानी है। ये विवरण निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उपलब्ध है। निर्वाचक नामावली की भाग संख्या निर्वाचक नामावली के दायें हाथ की ओर संबसे ऊपर कोने में मुद्रित होती हे। प्रत्येक प्रविष्टि को एक क्रम संख्या दी गयी है। कृपया निर्वाचन नामावली की जाँच करें और वह क्रम संख्या लिखें जिसमें उस व्यक्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, सूचीबद्ध है। यदि पहले ही उस व्यक्ति को पहचान–पत्र जारी किया जा चुका है तो उसकी संख्या भी उस प्रविष्टि के सामने मुद्रित होगी। कृपया दिए गए स्थान में उस पहचान–पत्र की पूरी संख्या लिखें।

किसी प्रविष्टि को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिये एवं किसी प्रविष्टि के विलोपन की अपेक्षा के लिए अलग- अलग आवेदन दिया जाना अपेक्षित है।

3. **आपत्तिकर्ता का विवरण –**

एक आपत्तिकर्ता प्रारूप–7 में केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में आवेदन दाखिल कर सकता है जिनका नाम निर्वाचन नामावली के उसी भाग में शामिल है, जहाँ आपत्तिकर्ता पंजीकृत है। आवेदन के दूसरे भाग में प्रदत्त स्थान में आपत्तिकर्ता को अपना नाम, उपनाम, सम्बंधी का नाम (पिता, माता, पति) लिंग, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या जिसमें उसका नाम पंजीकृत है, उल्लिखित करना है।

आपत्तिकर्ता को आवेदन के तीसरे भाग में दिए गए खाली स्थान में अपना पूरा पता भरना होगा।

4. **आपत्ति / विलोपन के कारण –**

आवेदन के चौथे भाग में आवेदक 'आपत्तिकर्ता' को स्पष्ट करना होगा कि उसके अनुसार जिसके नाम पर आपत्ति का जा रही है वह निर्वाचक नामावली के उस भाग में शामिल किए जाने के लिए क्यों निरर्ह है अर्थात मृत्यु हो जाने के कारण, स्थानान्तरण के कारण या पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण इत्यादि। नाम के विलोपन के लिए दिए गए कारणों को प्रमाणित करने के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने का दायित्व आपत्तिकर्ता का होगा।

5. **घोषणा –**

आवेदन के पाँचवें भाग में आवेदक को अनिवार्यतः घोषणा करनी होती है कि आवेदन में दिए गए सभी तथ्य एवं विवरण आवेदक के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदक वह तारीख सूचित करें जब से वह उस दिए हुए पते पर रह रहा है। असत्य घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–31 के अन्तर्गत दण्डनीय है।